कॉलेजियम और पारदर्शिता

साभार: द हिन्दू
(01 नवंबर, 2017)

सुहृथ पार्थसारथी
(अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

यह पहल एक तंत्र में सम्मान का एक लिबास शामिल करता है, जिसका थोड़ा संवैधानिक आधार भी है।

3 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अदालत की वेबसाइट पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए नामांकित व्यक्तियों पर इसके फैसलों सहित, उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अपनी पसंद और विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों के हस्तांतरण के फैसले भी जारी करने का फैसला लिया है। ये परिणाम, जो संकल्प जोड़ा गया है, कॉलेजिएम के विकल्पों के साथ शामिल होगा।

शुरुआत में यह पहल आवश्यक और महत्वपूर्ण है, जिससे अस्पष्टता के लिए बदनाम रहे इस तंत्र में पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन जब कॉलेजियम की ओर से जारी किए गए प्रकाशनों के पहले सेट के बारे में गहराई से जांच की गयी, तो यह स्पष्ट हुआ कि यह पहल एक तंत्र में सम्मान का एक लिबास शामिल करता है, जिसका थोड़ा संवैधानिक आधार भी है।

परेशान कारणों: कुछ कारणों पर गौर करें, जो इस प्रकार अब तक व्यक्त किए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार ए. जाकिर हुसैन और डॉ. के. अरुल के नामांकन में, कॉलेजियम ने प्रतिशब्द अस्वीकृति के निम्नलिखित बयान प्रकाशित किए: रिकॉर्ड पर सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इंटेलिजेंस ब्यूरो [आईबी] की रिपोर्ट सहित वे उच्च न्यायालय के खंडपीठ की पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आईबी की रिपोर्टों में और रिकॉर्ड में क्या शामिल हो सकता है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। फिर भी इन कारणों से संदेह हो सकता है कि आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के एक न्यायिक सदस्य वासुदेवन वी.एन. के नामांकन को खारिज करने की पेशकश की गई है, जो विशेष रूप से हैरान करने वाली बात हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दो सहयोगी-सहकर्मियों में से एक ने अपनी उपयुक्तता के बारे में कोई राय नहीं दी है और अन्य सहयोगी ने इसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया, रिपोर्ट में लिखा है। रिकॉर्ड के अनुसार, 28.11.2016 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की भी सिफारिश की गई थी और पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी असहमति व्यक्त कर दी। हमारे सामने रखा गया रिकार्ड यह भी दर्शाता है कि पिछले एक अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट के कॉलेजियम द्वारा उठाए गए अपने उन्नयन के प्रस्ताव को 1 अगस्त, 2013 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस तथ्य को इंगित करने वाली एक शिकायत भी कार्यालय में प्राप्त हुई है। परामर्श देने वाले न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए और कॉलिजियम के रिकॉर्ड के अनुसार माना जाता है कि श्री वासुदेवन वी. नदाथुर उच्च न्यायालय के खंडपीठ के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

अन्य सवाल: कॉलिजियम, जो कि शुरूआत के बाद से ही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद द्वितीय न्यायाधीशों के मामले (1993) के रूप में जाना जाता है, हमेशा से रहस्मयी रहा है। वर्तमान में हुए खुलासे, उनके कथित उद्देश्य का बहुत विरोध करते हैं, जो इस प्रणाली कि अपारदर्शिता को दर्शाता हैं। उदाहरण के लिए, श्री वासुदेवन के मामले में हमें नहीं पता है कि परामर्श देने वाले न्यायाधीशों (संभवत: सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों में से एक और इस मामले में इन्होने पहले मद्रास उच्च न्यायालय में सेवा की है) पर आपत्ति जताई हो और सवाल यह है कि आखिर क्यों न्यायाधीश इन्हें अनुपयुक्त पाएंगे। इसके अलावा, कॉलेजियम के व्यक्तित्व का यह उल्लेख है कि श्री वासुदेवन को पहले दो अलग-अलग उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित किया गया था, जिसका मतलब यह हुआ कि सभी में तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने विभिन्न बिंदुओं पर, उन्हें चयन के योग्य पाया। लेकिन, अब हम सोच रहे हैं कि कैसे एक सलाहकार न्यायाधीश का दृष्टिकोण, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तीन अलग-अलग उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों की राय को नामंजूर कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए नियोजित प्रणाली से संबंधित ये मुद्दे, भले ही वे अक्सर अस्पष्ट प्रक्रिया के मामलों को शामिल करते हो, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका को संविधान के निर्माताओं द्वारा सामाजिक क्रांति के केंद्र के रूप में माना जाता था। दरअसल, इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक 'द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन', में बताया है कि 'संविधान के न्यायिक प्रावधानों के निर्धारण के लिए एक आदर्शवाद केवल मूलभूत अधिकारों की दिशा में दिखाया गया है।' इसमें न्यायपालिका को दर्शाया गया है कि औपनिवेशिक दिनों के दौरान भारतीयों को समानता के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन यह प्राप्त नहीं होता था।

व्याख्यान परामर्श: इसके निपटन के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जजों को राजनीतिक प्रभाव से पृथक किया जाए, विधानसभा न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक परामर्श प्रक्रिया पर सहमत हो गई, जो एक मध्यम पाठ्यक्रम, है जैसा की बीआर आंबेडकर ने इसकी व्याख्या की थी। संविधान ने विधायी हस्तक्षेप की बोझिल प्रक्रिया और मुख्य न्यायमूर्ति को वीटो के लोकतांत्रिक प्रावधान से परहेज रखा और राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों की नियुक्तियों और हस्तांतरण दोनों के लिए शक्ति प्रदान की। राष्ट्रपति, जो मंत्रियों की परिषद की सलाह पर कार्रवाई करेंगे, हालांकि, इन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सहित कुछ अधिकारियों से अनिवार्य रूप से परामर्श करने की और उच्च न्यायालय में नियुक्ति करते समय, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की आवश्यकता है।

मूल रूप से 1977 में संकल्पचंद शेठ के मामले में, जब परामर्श शब्द की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शब्द का कभी मतलब नहीं, सहमति हो सकता है इसलिए, सीजीआई की राय, अदालत ने फैसला सुनाया, कार्यकारी बोर्ड पर बाध्य नहीं था। लेकिन फिर भी कार्यकारी अपनी राय से केवल असाधारण परिस्थितियों में हो सकता है और ऐसे मामलों में, इसका निर्णय अच्छी तरह से न्यायिक समीक्षा की कठोरता के अधीन हो सकता है, यह बिल्कुल सही संतुलन की तरह लग रहा था।

और वास्तव में, 1981 में, प्रथम न्यायाधीशों के मामले में अदालत ने एक बार फिर इस व्याख्या का समर्थन किया, हालांकि आंशिक रूप से लेकिन बारह साल बाद, द्वितीय न्यायाधीशों के मामले में, अदालत ने अपने पहले फैसलों को खारिज कर दिया, अब यह माना जाता है कि परामर्श वास्तव में सहमति का मतलब है, और यह कि सीजीआई के दृष्टिकोण को प्राथमिकता प्राप्त है, क्योंकि वह उम्मीदवारों के मूल्य जानने और मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर हैं। लेकिन, सीजेआई बदले में, वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक शरीर के माध्यम से अपनी राय तैयार करना था, जिसे अदालत ने कॉलेजियम के रूप में वर्णित किया।

1998 में, तीसरे न्यायाधीशों के मामले में अदालत ने अपनी स्थिति को आगे स्पष्ट कर दिया। जिसमें यह कहा गया है कि यह उच्चतम न्यायालय, सीजीआई और उनके वरिष्ठ सहयोगियों को नियुक्तियों के मामले में शामिल होगा। और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के मामले में, सीजीआई और उनके वरिष्ठ सहयोगी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों में अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम को ऐसे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय में सेवा करते हैं, जिन्होंने पूर्व में संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। हांलाकि, यह नया प्रस्ताव उपयुक्त मालूम पड़ता है जो इस प्रणाली में व्याप्त अपारदर्शिता को काफी हद तक समाप्त करने में सफल हो सकता है।

संबंधित तथ्य

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायपालिका की सलाह से कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। इस संबंध में अनुच्छेद 124 और 217 प्रासंगिक प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के प्रधान न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जायेगा।
- अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित।
- अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

कॉलेजियम व्यवस्था?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। उच्च न्यायालय के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में। वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था के अध्यक्ष चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं और जस्टिस जे. चेलामेश्वरम, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके सदस्य हैं।

विवाद?

- दरअसल, कॉलेजियम पाँच लोगों का समूह है और इन पाँच लोगों में शामिल हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीश। कॉलेजियम के द्वारा जजों के नियुक्ति का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है।
- कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर विवाद इसलिये है क्योंकि यह व्यवस्था नियुक्ति का सूत्रधार और नियुक्तिकर्त्ता दोनों स्वयं ही है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका की भूमिका बिल्कुल नहीं है या है भी तो बस मामूली।

सुधार के प्रयास

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था।
- उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केन्द्रीय विधि मंत्री और दो जानी-मानी हस्तियाँ भी इस आयोग का हिस्सा थीं।
- आयोग में जानी-मानी दो हस्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे।
- आयोग से संबंधित एक दिलचस्प बात यह थी कि अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।

संभावित प्रश्न

न्यायपालिका में कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर प्रायः सवाल उठते रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हवाला देकर हमेशा से इसका बचाव किया जाता रहा है। इस कथन के सन्दर्भ में इस प्रणाली के गुण और दोषों का विश्लेषण कीजिये।

In the judiciary, questions have often been raised about the collegium system, but it has always been defended by citing 'independence' of the judiciary. In relation to this statement, critically analyse the merits and demerits of collegium system. (200 words)